

ट्रंप की धमकी आर्थिक तनाव का कारण

ट्रंप ने डॉलर को किनारे छोड़ने के प्रयासों पर धमकी दी है जिससे वैश्विक आर्थिक तनाव पैदा हो गया है। अभी ट्रंप का राष्ट्रपति कार्यकाल शुरू होना है, पर निर्वाचित राष्ट्रपति ने अमेरिकी नीति पर अपने विचार प्रकट किए हैं जो विकासशील देशों के लिए अच्छी खबर नहीं हैं। निर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों-ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका व उनके विस्तारित गठबंधन को कठोर चेतावनी दी है जो अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व को चेतावनी दे रहे हैं। ट्रंप की घोषणा संभावित इन देशों से आने वाले सामानों पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने से संबंधित है जिससे वैश्विक स्तर पर आर्थिक तनाव पैदा हो गया है क्योंकि ब्रिक्स डॉलर का विकल्प तलाश रहा है। इस कदम से अमेरिका और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के बीच टकराव पैदा हो गया है जो विश्व व्यापार संरचना को बदल सकता है। उम्मीद थी कि ट्रंप अमेरिका को कर्ज से बाहर निकालने के सभी संभव प्रयास करेंगे तथा उन देशों पर कठोर कदम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे जो अमेरिका से मित्रता के बावजूद उसके हितों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। दशकों से अमेरिकी डॉलर विश्व व्यापार का केन्द्र रहा है और व्यापार में व्यापक प्रयोग के कारण इसे अधिकांश देशों के लिए रिजर्व मुद्रा समझा जाता है। लेकिन ब्रिक्स देशों तथा अन्य विकासशील अर्थव्यवस्थाओं ने विश्व वित्तीय व्यवस्था पर व्यापक नियंत्रण के प्रति बढ़ती निराशा प्रकट की है।



ब्रिक्स समूह में शामिल देश पहले ही नई विश्व मुद्रा लाने या डॉलर पर निर्भरता घटाने के लिए अपनी स्थानीय मुद्राओं के विस्तारित प्रयोग की चर्चा कर रहे थे। इस बात में कोई संदेह नहीं कि ट्रंप द्वारा ब्रिक्स देशों पर शत प्रतिशत टैरिफ लगाने की धमकी एक संरक्षणवादी प्रयास है और वे अमेरिकी आर्थिक हितों की रक्षा के लिए अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं। वास्तव में ट्रंप को ऐसे कठोर निर्णयों की जरा भी चिन्ता नहीं है, भले ही सारी दुनिया उनकी विरोधी क्यों न हो जाए। पर्यावरण, व्यापार या सैनिक खर्चों, आदि के मामलों में ट्रंप ऐसे निर्णय लेने में सक्षम हैं जिन पर सारी दुनिया आगबबुला हो सकती है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि डॉलर का प्रभुत्व घटाने का कोई भी प्रयास गंभीर नतीजों को जन्म देगा जिसमें अमेरिकी बाजार से बहिष्करण भी शामिल है। विकसित देशों के लिए बड़ी समस्या यह है कि वे अपनी आमदनी तथा राजस्व प्राप्त करने के लिए बड़ी सीमा तक अमेरिकी बाजार पर निर्भर हैं। ऐसे में ट्रंप द्वारा वैश्विक दक्षिण समेत अपने सहयोगियों व प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ दंडात्मक उपाय लागू करने की घोषणा चिन्ताजनक है, फिर चाहे वे ऐतिहासिक रूप से अमेरिका से जुड़े रहे हों। ऐसे टैरिफ के व्यापक प्रभाव होंगे। इससे विश्व व्यापार प्रवाह में बाधा आएगी तथा आर्थिक तनाव बढ़ेगा जिससे विकासशील देश अलग-थलग होंगे। शत-प्रतिशत टैरिफ से अमेरिका को निर्यात होने वाली वस्तुओं की कीमत बढ़ेगी जिसका प्रभाव अमेरिकी उपभोक्ताओं पर निर्भर उद्योगों पर पड़ेगा। ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसी अर्थव्यवस्थाएँ निर्यात पर अत्यधिक निर्भर हैं और इस कदम से उनमें आर्थिक मंदी आ सकती है। लेकिन विडंबना है कि भले ही ट्रंप की धमकियाँ अनेक देशों के लिए हानिकारक हों, पर वे डॉलर का विकल्प तलाशने में और गतिशील होंगे। इसके साथ ही ट्रंप के कट्टरपंथी दृष्टिकोण से विकासशील देश एकसाथ आ सकते हैं। इससे ब्रिक्स समूह तथा अन्य समूह और मजबूत हो सकते हैं। वास्तव में टैरिफ की दीवाल ऊंची करना आज की दुनिया में अच्छी बात नहीं मानी जाती है, लेकिन ट्रंप की अपनी सोच बिल्कुल अलग है।

चुनावी खैरातें: चिन्ता का विषय

चुनावों में खैरातें बांटने की बढ़ती प्रवृत्ति वित्तीय टिकारूपन, प्रशासन तथा मतदाताओं की सोच पर इसके प्रभाव को देखते हुए चिन्ता का विषय है।



उत्तम गुप्ता (लेखक, नीति विश्लेषक हैं)



हाल ही में महाराष्ट्र और झारखंड में हुए चुनावों में संबंधित राजनीतिक पार्टियों की सफलता का प्रमुख कारण खैरातें, यानी 'मुफ्त दी जाने वाली चीजें' हैं जो खासतौर से महिलाओं को लक्षित थीं। महाराष्ट्र में भाजपा नीत महायुक्ति गठबंधन ने 'लड़की बहन नकद लाभ योजना' शुरू की जिसमें 2,50,000 रुपये वार्षिक से कम आय वाले परिवारों में 21 से 65 आयुवर्ग की महिलाओं को 1,500 मासिक देने का प्रस्ताव था। बाद में इस धनराशि को बढ़ा कर 2,500 रुपये कर दिया गया था। झारखंड में 'मुख्यमंत्री मईयां सम्मान योजना'-एमएमएसवाई के अंतर्गत हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली जेएमएम-कांग्रेस-राजद सरकार ने 18-25 आयुवर्ग वाली सभी महिलाओं को 1,000 रुपये मासिक देने की योजना बनाई थी। बाद में इसकी धनराशि बढ़ा कर 2,500 रुपये महीने कर दी गई। खैरातों के माध्यम से चुनाव जीतने की प्रवृत्ति हर राज्य विधानसभा चुनाव में 2020 के बाद से दिखाई दे रही है, जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अपनी इसे राजनीतिक शैली से पंजाब में 2022 में विजय प्राप्त की थी। वहां आम आदमी पार्टी-आप ने 18 वर्ष या इससे अधिक आयु वाली हर महिला को 1000 रुपये प्रति माह जमा करने का वादा किया था। 2023 के शुरू में कर्नाटक में हुए चुनावों में कांग्रेस ने पांच गारंटियों का वादा किया था जिसमें 'गृह लक्ष्मी' योजना का बहुत प्रचार हुआ था। इसके अंतर्गत हर परिवार को महिला प्रमुख को 2000 रुपये प्रति माह दिए जाने थे। बाद में 2023 में मध्य प्रदेश में हुए चुनाव में भाजपा ने 'लाडली बहना योजना' के अंतर्गत 1,25,000 रुपये का वादा किया जिसे बाद में बढ़ा कर धीरे-धीरे 3,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया। छत्तीसगढ़ में उसने 'महत्तारी वंदन योजना' के अंतर्गत विवाहित महिला को 12,000 रुपये प्रति वर्ष देने का वादा किया। ओडिशा में 'सुभद्रा योजना' के अंतर्गत भाजपा ने सक्षम महिलाओं को हर साल दो किरतों में कुल 10,000 रुपये देने का वादा किया। भावी चुनावों में सभी पार्टियों से ऐसी ही खैरातें पर योजनाएँ लाने की आशा है। 2024-25 के

वर्ष से अधिक आयु वाली प्रति महिला को स्पष्ट रूप से वित्तीय अनियमितता है जिसका उद्देश्य मतदाताओं को सार्वजनिक धन से शक्ति देना है ताकि चुनावी राजनीति में लाभ प्राप्त हो सके। ऐसा भ्रष्ट व्यवहार से भी बहुत खराब है जो मतदाताओं को ललचाने के लिए सीधे पैसा बांटा हो। दूसरा, नियोजित तथा राजस्व प्राप्त से संशुद्ध व्यक्तित्व उम्मीदवार द्वारा किए व्यवहार से भी बहुत खराब है जो मतदाताओं को ललचाने के लिए सीधे पैसा बांटा हो। पूर्ण विकास खर्च समेत अनेक अन्य खर्चों में 'सामान्य' बजट खर्चों की तुलना में चुनावी घोषणापत्रों में वादा की गई खैरातों से राज्यों के बजट पूरी तरह 'अनियोजित' और 'अनियोजित' हो जाते हैं। अनियोजित होने के कारण इस खर्च के लिए राजस्व सृजन की कोई व्यवस्था नहीं होती है और इसकी कर्नाटक में पांच गारंटियों के कारण राज्य के कटौती के माध्यम से की जाती है। इसके साथ ही इससे अतिरिक्त कर्ज लेना पड़ सकता है और कर्ज असाधारण स्तर पर पहुंच सकते हैं। पंजाब में आप द्वारा खैरातों के वादों के कारण प्रति वर्ष 20,000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च होता है। बजट से इस खर्च की पूर्ति करने में अक्षम मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केन्द्र सरकार से 50,000 करोड़ रुपये की सहायता मांगी है। दिल्ली में प्रति माह 18

12.5 मिलियन लाभार्थी हैं जिनसे सरकारी खजाने पर प्रति वर्ष 18,750 करोड़ रुपये का बोझ पड़ता है। यदि सहायता बढ़ा कर 3,000 रुपये प्रति माह कर दी जाए तो यह 45,000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष हो जाएगा। महाराष्ट्र में लड़की बहन योजना से राज्य के खजाने पर हर साल 46,000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। झारखंड व ओडिशा जैसे राज्य भी खैरातों का बोझ अनुभव कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि जहाँ सामान्य कल्याण योजना में समाप्त करने की कोई तारीख होती है, पर खैरातों के मामलों में ऐसी कोई तारीख नहीं होती है। इसलिए वे 'हमेशा' लागू रहती हैं, भले ही किसी पार्टी का शासन हो और इसका राज्य के बजट पर लगातार बोझ पड़ता है। खैरातों के लिए पैसा करदाताओं की जेब से जाता है। जब उनको पता चलता है कि उनके टैक्स का पैसा लोगों को खैरातें बांटने में खर्च होता है तो इससे उनमें कर्ष न देने की प्रवृत्ति पैदा हो सकती है। अधिकांश मूलभूत जरूरतें 'हमेशा' पूरी होने के लिए वित्तीय सहायता का आश्वासन मिलने के कारण खैरातों की संस्कृति लोगों में काम के प्रति लापरवाही पैदा करने का कारण बन सकती है। इससे आर्थिक प्राप्ति की नींव पर प्रहार होता है। इसे स्थिति को देखते हुए राजनीतिक पार्टियाँ स्वयं कभी खैरातें बांटना नहीं छोड़ेंगी। क्या सर्वोच्च न्यायालय उनको ऐसा करने के लिए मजबूर कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय ने ए.एस. सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु सरकार एवं अन्य में जुलाई, 2013 में कहा था कि खैरातों का किसी प्रकार का वितरण सभी लोगों को प्रभावित करता है। उसने कहा, 'इससे बड़ी सीमा तक स्वतंत्र एवं स्वच्छ चुनावों का जड़ों पर प्रहार होता है। लेकिन चुनाव घोषणापत्र में किए वादों को लोक प्रतिनिधित्व का न्याय कानून या किसी अन्य कानून के अंतर्गत भ्रष्ट व्यवहार नहीं कहा जा सकता है। इसलिए सत्तारूढ़ दलों द्वारा राज्य विधानसभा में विनियोग विधेयकों के माध्यम से स्वीकृत खैरातें वितरण पर रोक नहीं लगाई जा सकती है।' सुप्रीम कोर्ट ने 25 जनवरी, 2022 को खैरातों पर एक जनहित याचिका को सुनवाई करते हुए अपने दृष्टिकोण में बदलाव नहीं किया। उसने कहा, 'निर्देश यह गंभीर मुद्दा है क्योंकि खैरातों के लिए बजट आम बजट से अधिक व्यय होता है।' लेकिन इस विषय पर लोक निर्माण विभाग ने टिप्पणियों से लाभ नहीं होगा। उसे सरकार को खैरातों पर लागू कर देना आदेश देना चाहिए।

सीखना निरंतर जारी रहे

शीखने को कला के रूप में समझना इसे एक सांसारिक कार्य से बदलकर आत्म-अन्वेषण और महारत की एक गहन यात्रा में बदल देता है, जिससे सीखने के लिए जुनून विकसित होता है जो कभी नहीं रुकेगा।

श्रीश्री श्री शर्मा (लेखिका शिक्षाविद हैं) सीखना एक जरूरी और आजीवन प्रक्रिया है। यह मानव विकास और विकास का आधारशिला है। हालाँकि, ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया से परे सीखने की सूक्ष्म कला है - एक दृष्टिकोण जो जिज्ञासा, रचनात्मकता, अनुकूलनशीलता और खोज के लिए जुनून पर जोर देता है। जिज्ञासा - शब्द अपने आप में आजीवन सीखने के लिए ईंधन है। इसके मूल में, सीखने की कला में लक्ष्यों और कौशल के संघ से कहीं अधिक शामिल है। यह एक गतिशील प्रक्रिया है जो बौद्धिक, भावनात्मक और अनुभवात्मक आयामों को एकीकृत करती है। सीखना तब कलात्मक हो जाता है जब यह उद्देश्यपूर्ण, आनंददायक और किसी व्यक्ति के मूल्यों



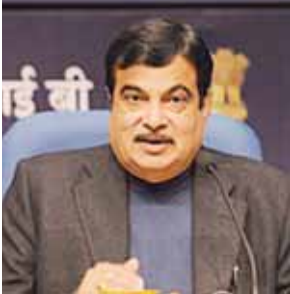
असफलताओं को अक्सर असफलताओं के बजाय सीखने के अवसर के रूप में देखा जाता है जबकि चुनौतियों को सीखने की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में स्वीकार किया जाता है। कोई कितना भी जानता हो, हमेशा बढ़ने की गुंजाइश होती है। विनम्र रहना, और दूसरों से प्रतिक्रिया, आलोचना और रचनात्मक इनपुट के लिए खुला रहना किसी व्यक्ति को अपनी समझ को बेहतर बनाने और परिष्कृत करने में मदद कर सकता है। सीखने की कला को बढ़ाने वाला एक और महत्वपूर्ण कारक जुनून की कला है। जो शिक्षार्थी अपनी रुचियों के अनुरूप विषयों का अध्ययन करते हैं, वे प्रवाह और स्थिति में प्रवेश करते हैं, जहाँ प्रयास सहज लगता है, और प्रक्रिया आंतरिक रूप से पुरस्कृत हो जाती है। जुनून प्रेरणा को बनाए रखता है और गहन जुड़ाव को बढ़ावा देता है, जिससे महारत हासिल होती है। अपने आप को समान विचारधारा वाले व्यक्तियों के साथ घेरना जो सीखने को प्राथमिकता देते हैं, चर्चाओं में शामिल होते हैं, कार्यशाळाओं में भाग लेते हैं या

परियोजनाओं पर सहयोग करते हैं, एक व्यक्ति को सीखने और बढ़ने के लिए चुनौती देते हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सबसे प्रतिभाशाली दिग्गज वाले लोग ऐसे सवाल पूछते हैं जिनसे दूसरे लोग हल्के में ले सकते हैं। किसी को क्यों और कैसे पूछने की आदत डालनी चाहिए और सवाल पूछने के लिए प्रेरणा और साहस की आवश्यकता है। सीखने की कला के रूप में समझना इसे एक सांसारिक कार्य से बदलकर आत्म-अन्वेषण और महारत की एक गहन यात्रा में बदल देता है, जिससे सीखने के लिए जुनून विकसित होता है जो कभी नहीं रुकेगा।

आप की बात - फ्लार्डओवर का मोह (जब भी हमारे नगरो में ट्रैफिक जाम का जिक्र होता है, प्रशासन और हमारे नेताओं का पहला और आखिरी जवाब होता है- फ्लार्डओवर बनाएँगे। सड़क पर जगह नहीं बची? ऐसा लगता है कि हर समस्या का समाधान सिर्फ ऊपर से ही निकाला जा सकता है। सड़कें गड़गड़ से भरी हों, सार्वजनिक परिवहन का नामो-निशान न हो, पर फ्लार्डओवर बना दो, सब ठीक हो जाएगा। फ्लार्डओवर ट्रैफिक समस्या का हल नहीं, बल्कि ऊपर से देखने का नजरिया है। फ्लार्डओवर का निर्माण हमारे बजट का ऐसा हिस्सा बन गया है, जैसे चाय में चीनी। सड़कों पर फ्लार्डओवर बनाना उतना ही जरूरी समझा गया है जितना राजनीति में वादे करना। पर सवाल ये है कि क्या ये फ्लार्डओवर सच में हमारी समस्याओं का समाधान हैं या सिर्फ आंखों का धोखा? सरकार और प्रशासन का फ्लार्डओवर प्रेम देखकर लगता है कि जमीन पर रहना उन्हें अपमानजनक लगता है। ऊपर चलने वालों का ही ऊपर नाम होता है, शायद यही सोचकर हर शहर/नगर में फ्लार्डओवर की बाढ़ आई है। लेकिन जरा सोचिए, इन फ्लार्डओवरों से क्या वाकई ट्रैफिक का हल निकलता है, या बस समस्या को ऊपर पहुंचा दिया गया है? जिस नगर में सड़कें गड़गड़ से भरी हों, जहाँ पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ का हल नहीं है, जैसे चाय में चीनी, वहाँ फ्लार्डओवर की चकाचौंध एक दिखावा भर है। -आर.के. जैन, बड़वानी) -इन्टरनेट पर अश्लीलता (संस्कार रहित शिक्षा किसी भी परिवार,जाति अथवा राष्ट्र के पतन का कारण बन जाती है। आज शिक्षा का उद्देश्य मात्र आर्थिक आधार बनकर रह गया है। दुर्भाग्य तो यह भी है कि परिवार भी संस्कारों से कोसों दूर होते नजर आ रहे हैं। दो वर्ष के होते-होते बच्चे के हाथ में मोबाइल आ जाता है। रही सही कसर आन लाइन शिक्षा ने पूरी कर दी। आज आए दिन पर्यावरण व मौसम को लेकर प्रशासन द्वारा विद्यालयों को बन्द करने और आन लाइन शिक्षा के आदेशों ने संस्कारों और अनुशासन की शिक्षा से दूर कर दिया है। जो बालक में अक्सर और एकपानता की पेट को बढ़ावा दे रहे हैं। इन्टरनेट पर आज अश्लील और अपारधिक सामग्री की भरमार है। जिस बालक को शैक्षिक प्रयोग के लिए माता पिता मोबाइल पकड़ा रहे हैं, अब उस बच्चे पर निर्भर करता है कि वो उसका प्रयोग किस शिक्षा के लिए कर रहा है? बच्चों का अपसंस्कृति की तरफ आकर्षित होने में माता-पिता भी बराबर के दोषी हैं। यह सुखद है इस समस्या की तरफ सबसे पहला क्रदम आस्ट्रेलिया जैसे देश ने बढ़ाया है। जहाँ की सरकार ने 16 वर्ष के कम आयु के बच्चों के लिए इन्टरनेट के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। अब देखा यह है कि भारत सरकार इस तरफ कब ध्यान देगी? क्योंकि अश्लीलता से बच्चों को बचना बहुत जरूरी है। नहीं तो उनके कोमल मन पर गलत प्रभाव पड़ेगा। -डॉ. नरेन्द्र टोंक, मेरठ।) -हाईब्रिड आयोजन ही निदान (पाकिस्तान के हालात बंद से बदतर हैं। राजनैतिक विवादों के कारण कई पाकिस्तानी शहरों में हिंसा हुई है। आत्मघाती हमले और सेना पर निशाने साधने से लोगों के साथ ही वहां होने वाले आयोजन भी खटाई में पड़ते दिख रहे हैं। हाल ही में इमरान खान के पार्टी कार्यकर्ताओं ने इस्लामाबाद में जिस तरह बवाल काटा उससे अगले साल वहां होने वाली चैम्पियंस ट्रॉफी के आयोजन पर संकट के बादल मंडराना शुरू हो गए हैं। सुरक्षा कारणों और राजनैतिक अशांति की वजह से श्री लंका ए को भी अपने दौरे को छोड़ कर स्वदेश लौटना पड़ा है। वहाँ के ताजे हालात इस बात को समझने के लिए काफी है कि ऐसे हालातों में वहाँ आयोजन कितने सुरक्षित रहेंगे? आने वाले दिनों में हो सकता है ट्रॉफी खेलने खेलने वाले अन्य देश भी इसी वजह से हाथ खड़े कर दें। भारत पहले ही पाकिस्तान में खेलने से मना कर चुका है। अब हाइब्रिड आयोजन ही एक मात्र उपाय है और इसके लिए प्रतिभागी देश सहमत भी हो जायेंगे। हाइब्रिड आयोजन के लिए पाकिस्तान का सहमत होना एक अच्छा संकेत है? अब इसी के अनुरूप कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जानी चाहिए। क्योंकि हमारे अपने ही नहीं, किसी देश के खिलाड़ियों की सुरक्षा को खतरों में नहीं डाला जा सकता है। पाकिस्तान की स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। -अमृतलाल मारू, इन्दौर) -जीवन अधिक महत्वपूर्ण (पर्वतारोहण पर सदियों से जान जोखिम में डालकर में डालकर लोग रोमांच का अनुभव करते हैं। सर्वप्रथम हिमालय पर पहुंचकर एडमंड हिलेरी और तेनजिंग शेर्पा ने दुनिया को रोमांचित कर दिया था। अब पर्वतारोहण के लिए कई हल्का आधुनिक संसाधन उपलब्ध हो गए हैं। और पुरुषों के साथ महिलाएं भी पर्वतारोहण कर रही हैं। जीने जीवन का असली रोमांच अनुभव करना है। जान की परवाह नहीं करते और अपनेजीवन का अधिकतम रोमांच अनुभव करते हैं।अब सिर्फ पर्वतारोहण ही नहीं वल्कि समुद्र की तलहटियों अंतरिक्ष

की ऊंचाइयों तक मानव अपनी जान की परवाह किए बिना भावी पीढ़ी के लिए नए रास्ते खोज रहे हैं। सुनीता विलियमस भी अंतरिक्ष में अपने जीवन केलिए संघर्ष कर रही हैं। यह आदिवासी पृथ्वी पर लौट आई है तो यह एक चमत्कार होगा और इतने लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली दुनिया की पहली महिला होगी! आगे भी मानव ने खतरों उठाकर नई-नई रोमांच लेता रहेगा! लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि जीवन को खतरों में डालकर कोई भी रोमांच अच्छा नहीं है। -विभूति बुक्क्या, खारचोद, पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से responsemail.hindipioneer@gmail.com पर भी भेज सकते हैं।

राजनीति असंतुष्ट आत्माओं का सागर है: गडकरी



नागपुर (महाराष्ट्र) केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि राजनीति असंतुष्ट आत्माओं का सागर है, जहां हर व्यक्ति दुखी है और अपने वर्तमान पद से उगे पद वीं आवंथा रहता है। नागपुर में रविवार को जीवन के 50 वर्षीय नितिन नामक पुस्तक के विमोचन के अवसर पर गडकरी ने कहा कि जीवन समझौते, बाध्यताओं, सीमाओं और विरोधाभासों का खेल है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता ने कहा कि चाहे व्यक्ति पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक या कॉर्पोरेट जीवन में हो, जीवन चुनौतियों और समस्याओं से भरा है और व्यक्ति उसे उनका सामना करने के लिए जीवन जीते वीं क्या वो समझना चाहिए। मंत्री ने राजस्थान में आयोजित एक कार्यक्रम को याद करते हुए कहा, राजनीति असंतुष्ट आत्माओं का सागर है, जहां हर व्यक्ति दुखी है... जो पारंगत बनता है वह इसलिए दुखी होता है क्योंकि उसे विश्वास बनने का मौक़ा नहीं मिला और विश्वासक इसलिए दुखी होता है क्योंकि उसे मंत्री पद नहीं मिला सच। भाजपा नेता ने कहा, जो मंत्री बनता है वह इसलिए दुखी रहता है कि उसे अच्छा मंत्रालय नहीं मिला और वह मुख्यमंत्री नहीं बन पाया तथा मुख्यमंत्री इसलिए तनाव में रहता है क्योंकि उसे नहीं पता कि वह आलाक़ान्मन उसे पद छोड़ने के लिए क्या देगा। उन्होंने कहा कि जीवन ने समस्याएं बढ़ी चुनौतियां पेश करती है और उनका सामना करना तथा आगे बढ़ना ही जीवन जीने वीं क्या है। गडकरी ने कहा कि उन्हें अपने राजनीतिक जीवन के अमेरिकी के पूर्व राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन वीं आलाक़था का एक उद्धरण याद है, जिसने कहा गया है, कोई व्यक्ति तब ख़त्म नहीं होता जब वह हार जाता है। वह तब ख़त्म होता है जब वह हार मान लेता है। केंद्रीय मंत्री ने सुबूची जीवन के लिए अच्छे मानवीय मूल्यों और संस्कारों पर जोर दिया। उन्होंने जीवन जीते और सफल होने के अपने आदर्शों तथा नियमों को साझा करते हुए व्यक्ति, पार्टी और पार्टी दर्शन के महत्व पर भी प्रकाश डाला।

न्यायालय ने मतदाता संख्या बढ़ाने पर निर्वाचन आयोग का रुख पूछा

नई दिल्ली। (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को निर्वाचन आयोग से उस जनहित याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1,200 से बढ़ाकर 1,500 करने के उसके फैसले को चुनौती दी गई है। प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार को पीठ ने निर्वाचन आयोग से अपना रुख स्पष्ट करने को कहा। उन्होंने कहा, हम चिंतित हैं। किसी भी मतदाता को वंचित नहीं किया जाना चाहिए। पीठ ने आयोग की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह को प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या बढ़ाने संबंधी फैसले का औचित्य स्पष्ट करते हुए एक संक्षिप्त हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। पीठ ने कहा, निर्वाचन आयोग की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने कहा है कि वे एक संक्षिप्त हलफनामे के जरिए स्थिति स्पष्ट करेंगे। हलफनामा तीन हफ्ते के भीतर दखिल किया जाए। सिंह ने कहा कि पीठ ईबीएम को लेकर लगातार



लगाए जा रहे आरोपों से वाकिफ है। उन्होंने कहा, आरोप लगते रहेंगे। 2019 से मतदान ऐसे ही हो रहा है और मतदाता संख्या बढ़ाने से पहले हर निर्वाचन क्षेत्र में राजनीतिक दलों से परामर्श किया जा रहा है। सिंह ने कहा कि मतदान केंद्रों पर कई मतदान बूथ हो सकते हैं और जब प्रत्ये ईबीएम मतदाताओं की कुल संख्या बढ़ाई गई, तो प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में राजनीतिक दलों से परामर्श किया गया। उन्होंने कहा कि मतदाताओं को निर्धारित समय के बाद भी हमेशा वोट डालने की अनुमति

दी गई। पीठ ने निर्वाचन आयोग को अगली सुनवाई से पहले याचिकाकर्ता को अपने हलफनामे को एक प्रति मुहैया करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी 2025 को होगी। इंदू प्रकाश सिंह की ओर से दायर जनहित याचिका में अगस्त में निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दो विज्ञप्तियों को चुनौती दी गई है, जिसमें पूरे भारत में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में प्रति मतदान केंद्र मतदाताओं की संख्या बढ़ाने की बात कही गई है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि प्रति मतदान केंद्र मतदाताओं की संख्या बढ़ाने का फैसला मनमाना है और यह किसी भी डेटा पर आधारित नहीं है। शीर्ष अदालत ने 24 अक्टूबर को निर्वाचन आयोग को कोई भी नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया था। हालांकि, उसने याचिकाकर्ता को आयोग के स्थाई वकील को याचिका को प्रति सौंपने की अनुमति दे दी थी, ताकि इस मुद्दे पर उसका रुख पता चल सके। याचिकाकर्ता की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने दलील दी कि मतदाताओं की संख्या 1,200 से

बढ़ाकर 1,500 करने से वंचित समूह चुनावी प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि किसी व्यक्ति को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए अधिक समय खर्च करना होगा। सिंघवी ने कहा कि मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें और प्रतीक्षा समय मतदाताओं को वोट डालने से हतोत्साहित करेगा हालांकि, पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग मतदान में अधिक भागीदारी चाहता है और ईबीएम के इस्तेमाल के साथ मतदान में मतपत्रों की तुलना में कम समय लगता है। उसने कहा कि आयोग का इरादा मतदान केंद्रों पर ईवीएम की संख्या बढ़ाकर वोट डालने में लगने वाले समय में कमी लाना है। हालांकि, याचिकाकर्ता ने कहा कि निर्वाचन आयोग का फैसला महाराष्ट्र और झारखंड के बाद 2025 में बिहार और दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनावों के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करेगा। उसने कहा कि आम तौर पर मतदान 11 घंटे होता है और एक वोट डालने में लगभग 60 से 90 सेकंड का समय लगता है>

संविधान पर मेरी टिप्पणी को मीडिया ने गलत तरीकेसे पेश किया : पेजावर मट के महंत

उडुपी (कर्नाटक) । श्री पेजावर मट के महंत श्री विश्वप्रसन तीर्थ स्वामीजी ने स्पष्ट किया है कि भारतीय संविधान पर उनकी टिप्पणी को मीडिया में गलत तरीके से पेश किया गया। स्वामीजी ने कहा कि उन्होंने कभी संविधान में बदलाव की मांग नहीं की और इसके सिद्धांतों के प्रति अपना सम्मान दोहराया। स्वामीजी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के न्यासी हैं। स्वामीजी ने रविवार को संवाददाता सम्मेलन में गलत सूचना पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर कटिपत्रों के मुख्यमंत्री सिद्धमैया की टिप्पणियों ने अनावश्यक भ्रम पैदा किया है। उन्होंने कहा, संविधान का सम्मान करता हूं और इसकी भावना के खिलाफ किसी भी पहल का कभी समर्थन नहीं किया है। विश्व हिंदू परिषद (विहिप) की कर्नाटक इकाई द्वारा 23 नवंबर को बेंगलुरु में आयोजित संत सम्मेलन में स्वामीजी के संबोधन के बाद विवाद उत्पन्न हो गया, जहां उन्होंने कथित तौर पर एक ऐसे संविधान की मांग की जो बहुसंख्यकों के हितों का सम्मान करता हो।

नक्काशीदार मूर्तियां बनेंगी महाकुंभ का आकर्षण

श्रद्धालुओं का स्वागत करेंगे अर्जुन, गरुड़, नंदी और ऐरावत-योगी सरकार के निर्देश पर 26 चौराहों को विशेष रूप देने की योजना

प्रयागराज। महाकुम्भ में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को इस बार आदिकालीन भारोगी संस्कृति की दिव्यता और अलौकिकता का दर्शन करा जा रहा है। आच पात्रे किसी भी परिवहन के माध्यम से प्रयागराज पहुंचें आपके स्वागत में स्वयं अर्जुन गरुड़ नंदी ऐरावत और मां गंगा के साथ ही श्रवण कुमार भी मौजूद रहेंगे। पौराणिक महत्व की ये 26 नक्काशीदार मूर्तियां महाकुम्भ में आने वाले देशी विदेशी श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र बनने जा रही हैं। जिन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रयागराज के 26 प्रमुख

सुपर डीलक्स होटल जैसी सुविधाओं से लैस होगी टेंट सिटी

प्रयागराज। प्रयागराज महाकुम्भ में आने वाले करोड़ों मत्रों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर योगी सरकार महाकुम्भ जिला क्षेत्र के सेक्टर बीस अरेल में दो हजार से ज्यादा रिसस कोर्टेज बेड टेंट की स्थापना कर रही है। इन टेंटों की स्थापना उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास मंत्रालय लिमिटेड यूपीएसटीडीसी द्वारा किया किया जा रहा है और छह पार्टनर्स के साथ मिलकर विभिन्न टेंट ब्लॉक की स्थापना कर रहे हैं। इनमें आगमन कुम्भ केरा पंडिया श्रद्धालु कुम्भ कोर्टेज कुम्भ विलेज कुम्भ केनवास व एर प्रमुख है। खास बात यह है कि वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स के अनुसार इन टेंट की स्थापना व संचालन की ज़ामाना जो फ्रवट स्टार डील वशी की सुविधाओं से लैस होंगी। यह सुपर डीलक्स टेंट बिला महाराजा रिसस कोर्टेज व डैलिट्टी केमैट में उल्लख रहेगी जिनका प्रसिधता 1500 से 35 हजार के बीच प्रतिदिन के हिसाब से तय रहेगी। वहीं डैलिट्टी के अलावा चार हजार से आठ हजार का शुल्क अतिरिक्त व्यक्ति के दखले पर देना होगा। यूपीएसटीडीसी द्वारा जो टेंट सिटी स्थापित की जा रही है वह शीघ्र ही योगी के विजन के अनुरूप तैयार की जा रही है। अनुमान है कि महाकुम्भ 2025 में 75 देशों के 45 करोड़ से अधिक विगिस्ट आ सकते है ऐसे में उन्हे वर्ल्ड क्लास अकॉमोडेशन फेसिलिटी उल्लख कराने के लिए एक जनवरी से 5 जार्वी की समन्वयि के बीच इन टेंट्स का संचालन किया जाएगा। इन टेंट को यूपीएसटीडीसी की वेबसाइट और महाकुम्भ ऐप के जरिह भी बुक किया जा सकता है।



चौराहों पर स्थापित करने का काम जोर-जोर से चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप इस बार के महाकुम्भ की दिव्य नव्य और भव्य बनाने की तैयारी चल रही है। इसके तहत पौराणिक एवं भारतीय संस्कृति के

महत्व की नक्काशीदार मूर्तियां शहर के प्रमुख चौराहों पर सजाई जा रही हैं। इनमें अर्जुन गरुड़ नंदी गदा के अलावा मां गंगा सहित तमाम ऐसी मूर्तियां हैं जो श्रद्धालुओं को आकर्षित करेंगी। एसडीएम मेला अभिनव पाठक ने बताया कि इस योजना के

तहत योगी सरकार के निर्देश पर 26 चौराहों को विशेष रूप से आकर्षक आकार दिया जा रहा है। इनमें 06 चौराहों पर काम पूरा किया जा चुका है। साथ ही एक सप्ताह के भीतर बाकी 20 चौराहों का काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। महाकुम्भ में

भाजपा ने विधायक बसनगौड़ा पाटिल को नोटिस दिया

बेंगलुरु।(भाषा) भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की केंद्रीय अनुशासन समिति ने एदियुरप्पा के कटु आलोचक माने जाने वाले विजयपुर के विधायक बसनगौड़ा पाटिल यतनाल को प्रदेश पार्टी नेतृत्व के खिलाफ लगातार तीखी टिप्पणी करने को लेकर कारण बताओ नोटिस दिया है और उनसे 10 दिन के भीतर जवाब देने को कहा है। कुछ दिन पहले ही यतनाल ने प्रदेश नेतृत्व की अनुमति के बगैर ही एक माह तक चलने वाला वक्फ विरोधी मार्च शुरु किया। नोटिस पर प्रतिक्रिया देते हुए यतनाल ने कहा कि हिंदुत्व के लिए लड़ाई और वंशवादी राजनीति के खिलाफ उनकी प्रतिबद्धता जारी रहेगी। केंद्रीय अनुशासन समिति के सदस्य सचिव ओम पाठक ने एक दि संबंघ को भेजे कारण बताओ नोटिस में कहा, प्रदेश पार्टी नेतृत्व के खिलाफ आपके तीखे हमले, पार्टी के

निर्देशों की अवहेलना और राजनीतिक तथा सार्वजनिक महत्व के सभी मामलों पर पार्टी के आधिकारिक रुख के विपरीत सार्वजनिक बयानबाजी तथा रुख अपनाने की खबरें मीडिया के साथ-साथ विभिन्न पार्टी मेंबर पर भी सामने आई हैं। ऐसे नोटिस मीडिया के साथ सोमवार को साझा किया गया। पार्टी ने बताया कि अगर यतनाल निर्धारित समय के भीतर जवाब नहीं दे पाते हैं तो वह इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय लेगी। यतनाल पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस. एदियुरप्पा और उनके परिवार, खासकर भाजपा की उनके खिलाफ अत्याचारों की जाई. विजयंद्र के कड़े आलोचक माने जाते हैं। वह अक्सर उन पर निशाना साधते हैं और भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से मांग करते रहते हैं कि कांग्रेस की परिवारवादी राजनीति के खिलाफ प्रभावी लड़ाई के लिए एदियुरप्पा की



वंशवादी राजनीति पर लगाम लगाई जाए। पाठक ने कहा, यह गंभीर चिंता की बात है कि अतीत में कई बार कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने और अच्छे आचरण के आपके

आश्वासन के बावजूद अनुशासनहीनता बेरोकटोक जारी है। पार्टी में उनकी वरिष्ठता की ध्यान में रखते हुए पार्टी ने कहा कि केंद्रीय अनुशासन समिति ने अतीत में उनके द्वारा दिए गए स्पष्टीकरणों पर नरम रुख अपनाया है। उन्होंने कहा, आपने पार्टी नेताओं के खिलाफ झूठे और परोक्ष आरोप लगाए हैं। आपने राजनीतिक और सार्वजनिक महत्व के मामलों पर पार्टी के आधिकारिक रुख की अवहेलना की है जो भाजपा के पार्टी नियम का गंभीर उल्लंघन है। पाठक ने यतनाल से कहा, कुपया कारण बताएं कि पार्टी को क्यों नहीं आपके खिलाफ अनुशासनत्मक कार्वाई करनी चाहिए? आपका स्पष्टीकरण इस नोटिस मिलने के दस दिन के भीतर पेश किया जाना चाहिए। निर्धारित समय में स्पष्टीकरण नहीं मिलने की स्थिति में केंद्रीय अनुशासन समिति यह मान

बांग्लादेश में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन तैनात करने और संसद में केंद्र के बयान

की मांग की ममता ने

कोलकाता। बांग्लादेश वीं वर्तमान स्थिति से विपति पश्चिम बंगाल वीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को वोट से इस पक्षीही दे को शांति मिशन तैनात करने के लिए संयुक्त राष्ट्र से संपर्क करने तथा प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी से वल से सहाए वा आभारिती को वापस लाने के लिए हस्तक्षेप करने वीं अपील की। बनर्जी ने यह भी मांग वीं कि विदेश मंत्री को बालादेव वीं वर्तमान स्थिति पर भारत के रक्ष से संसद को अवगत कराना चाहिए। उन्होंने क्हा, अगर प्रधानमंत्री मोदी खूद यह काम करने के लिए उल्लख नही होते है, तो विदेश मंत्री वा बहाना वर्तमान शिवालयीन सत्र के दौरान आना चाहिए। शिवालयना को संबोधित करते हुए बनर्जी ने कहा कि दोनों देशों के बीच के द्विपक्षीय मुद्दे पर टिप्पणी करना उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, क्योंकि बंगाल देश वीं सीधी व्यवस्था में केवल एहत साज है। उन्होंने कहा, हालांकि, हाल के घटनाक्रमों और जिन लोगों के बांग्लादेश में हिस्तेदार और ठिकाने है।

पेज 1 का शेष

संविधान..

संकट को उठाएगी। हालांकि, सरकार के सूत्रों ने कहा कि कांग्रेस को अलगी विवाद पर विशेष चर्चा की अनुमति नहीं दी जाएगी, लेकिन अगर विपक्षी सदस्य किसी भी बहस के बीच में इसके बारे में संकेत देते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी।

एनसीआर...

के बीच निर्माण गतिविधियों के रुकने से प्रभावित हुई है। दिल्ली-एनसीआर को हर साल अक्टूबर से दिसंबर के बीच पड़ती ही स्थिति का सामना करना पड़ता है, इस पर गौर करते हुए पीठ ने वायु प्रदूषण के सभी पहलुओं पर विचार करने और स्थायी समाधान खोजने का प्रस्ताव रखा। हितधारकों के बीच समन्वय की कमी का जिक्र करते हुए पीठ ने प्रतिबंधों को लागू करने में दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस, दिल्ली नगर निगम और प्रदूषण नियंत्रण समिति सहित हितधारकों के बीच 'समन्वय की पूर्ण कमी' को उजागर किया और

प्रतिबंधों में ढील देने पर फैसला करने से पहले बुधस्मतिवार तक इंतजार करने का फैसला किया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वायु प्रदूषण के स्तर में वास्तव में लगातार गिरावट का रझान है। पीठ ने कहा, 'हम जो प्रस्ताव देते हैं, वह यह है कि हम आपके सुझावों पर गौर करेंगे, लेकिन आज हम तब तक ढील नहीं देंगे जब तक आप हमें स्पष्ट गिरावट का रझान नहीं दिखाते।' ऐसे ही एक कोर्ट कमिश्नर की दुर्दशा का जिक्र करते हुए पीठ ने पुलिस से अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। पीठ ने कहा, 'हम बार के सदस्यों को जोखिम में नहीं पड़ने दे सकते, क्योंकि रिपोर्ट से पता चलता है कि उनके से कुछ को धमकीयों दी गई हैं।' पीठ ने पूछा कि क्या कोर्ट कमिश्नर काम जारी रखना चाहते हैं और वे लोग काम जारी रखना चाहते हैं, वे दिल्ली पुलिस द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी को इमेल भेजें। शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि कोर्ट कमिश्नरों को उनके कर्तव्यों का निर्वहन करते समय सशस्त्र गाड़ों सहित पुलिसकर्मों दिए जाएँ। पीठ ने कहा, 'हम यह स्पष्ट करते हैं कि यह सुनिश्चित करना दिल्ली पुलिस की

जिम्मेदारी है कि कोर्ट कमिश्नर के रूप में काम करने वाले बार के सदस्यों को पर्याप्त सुरक्षा मिले।' कोर्ट कमिश्नर जतिन कुमार और सानी नागपाल ने झारोदा टोल पर उल्लंघन की सूचना दी, जहाँ निर्माण और विवर्धन (सीएंडई) सामग्री ले जाने वाला एक बीएस-फोर डीजल ट्रक बिना वैध दस्तावेज के दिल्ली में प्रवेश कर गया। एक अन्य न्यायालय आयुक्त ने अपनी रिपोर्ट में 29 नवंबर, 2024 को नई दिल्ली के खेलगॉंव स्थित एशियाड विलेज में हुई एक घटना का विवरण दिया है। उन्होंने एक निर्माण कंक्टिंग मशीन को 'भेल' नेमप्लेट वाली एक संपत्ति पर काम करते देखा। तस्वीरें लेने का प्रयास करने पर, उन्होंने घर के अंदर भाग रहे श्रमिकों को देखा। इस बीच, दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएफ्यूएम) ने न्यायालय को एक रिपोर्ट सौंपी, जिसमें आपातकालीन उपायों को ग्रेप-4 से घटाकर ग्रेप-2 करने की मांग की गई, क्योंकि 32 दिनों तक गंभीर (400+) या बहुत खराब (300+) क्षेत्रों में रहने के बाद 1 दिसंबर को एक््यूआई 285 (खराब) था। बेंच ने टिप्पणी की,

'राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रेप के चरण 4 का शायद ही कोई कार्यान्वयन हो रहा है' दिल्ली सरकार से प्रतिबंधों को लागू करने के लिए तैनात अधिकारियों की संख्या पर सवाल उठते हुए, विशेष रूप से ट्रकों को राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करने से प्रतिबंधित करना। दिल्ली सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शादान फरसत ने कहा कि वह जीआरएपी प्रतिबंधों का पालन करने के आरोपों की जांच करेगी। पीठ ने सीएफ्यूएम को निर्देश दिया कि वह सभी संबंधित अधिकारियों को शमन उपायों के बारे में सूचित करने के लिए कदम उठाए, जिन्हें लागू करने का उसने फैसला किया है और कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए समन्वय करें।

महाराष्ट्र...

अनिच्छुक हैं। हालांकि, शिंदे ने कथित तौर पर फडणवीस के मुख्यमंत्री रहते उपमुख्यमंत्री का पद स्वीकार करने के लिए गृह विभाग को एक पूर्व शर्त बना दिया है।

सेथिल..

दिसंबर को तय की पीठ ने

उल्लेख किया कि शिकायतकर्ताओं में से एक के विद्या कुमार द्वारा दायर वर्तमान याचिका एस आशंका पर आधारित थी कि जमानत दिए जाने के तुरंत बाद बालाजी को कैबिनेट मंत्री नियुक्त कर दिया गया था।

एक दुखद...

चालक मंत्रोगौड़ा को मामूली चोट आई। पुलिस ने बताया कि आईपीएस अधिकारी ने हाल ही में मैसूर में कर्नाटक पुलिस अकादमी में अपना चार सप्ताह का प्रशिक्षण पूरा किया था। उनके पिता एक उप-विभागीय मजिस्ट्रेट हैं। '

पाक नेवी.....

भारतीय नौसेना इस पर कड़ी नजर रख रही है। चार दिसंबर को नौसेना दिवस से पहले एक वार्षिक सम्मेलन में ये दावे करते हुए एडमिरल त्रिपाठी ने कहा कि चीन और पाकिस्तान की नौसेनाओं की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है।

दिल्ली एयर...

से प्रभावित यात्रियों के दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे। डायल

कानपुर देहात में क्रोमियम प्रदूषण तत्काल दूर करने की जरूरत: रिपोर्ट

नई दिल्ली। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) को प्राप्त एक रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात और फतेहपुर जिलों में लोग मिट्टी और जल से संबंधित क्रोमियम प्रदूषण का सामना कर रहे हैं जिसे तत्काल दूर करने की जरूरत है। हरित अधिकरण ने इसके पहले एमिकस क्यूरी (अदालत मित्र) से रिपोर्ट मांगी थी। एनजीटी कानपुर देहात के रनिया और कानपुर नगर के राखी मंडी में क्रोमियम युक्त कचरे को वैज्ञानिक रूप से निपटाने में संबंधित अधिकारियों की विफलता के मुद्दे पर सुनवाई कर रहा था।अधिकरण ने कानपुर नगर के जाजमऊ में ठीक से काम नहीं कर रहे कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) के माध्यम से सिंचाई नहरों में जहरीले क्रोमियम युक्त औद्योगिक अपशिष्टों को छोड़ने वाली ठेकी द्वारा निरंतर जल प्रदूषण और फतेहपुर जिले के गोधरीली गांव में उद्योगों द्वारा भूजल में क्रोमियम प्रवाहित किए जाने के मुद्दे को एक साथ जोड़ दिया। अदालत मित्र काव्थायनी ने 26 नवंबर की दिनांक वाली एक अंतरिम रिपोर्ट में कहा कि उन्होंने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उग्र जल निगम और मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों के साथ कानपुर देहात, कानपुर नगर, फतेहपुर और 19 से अधिक अन्य स्थानों का दौरा किया। रिपोर्ट के अनुसार तीनों जिलों में से प्रत्येक के अलग-अलग मुद्दे हैं। उदाहरण के लिए कानपुर नगर में सीवेज उपचार संयंत्र (एसटीपी) काम नहीं कर रहा है, जबकि कानपुर देहात और फतेहपुर में कोई एसटीपी ही नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया है, इसी तरह, कानपुर देहात और फतेहपुर में मिट्टी और भूजल में क्रोमियम प्रदूषण की समस्या है जिसे तत्काल दूर करने की जरूरत है। इसमें यह भी कहा गया है कि प्रयागराज में आर्सेनित होने वाले आगामी महाकुंभ को ध्यान में रखते हुए गंगा और पांडु नदियों के प्रदूषण को रोकने के लिए एक अस्थायी कार्य योजना अपनाई जानी चाहिए।

उत्तर प्रदेश सरकार सिलिक रेत खनन इलाकें में विशिष्ट स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराए : एनजीटी

नई दिल्ली। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने उत्तर प्रदेश सरकार को उन क्षेत्रों में विशिष्ट स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करने का निर्देश दिया है, जहां निजी पट्टाधारक सिलिका रेत का खनन कर रहे हैं। अधिकरण शंकरगढ़, परवेजाबाद, लालापुर, बांकीपुर, जनवा और धारा सहित प्रयागराज जिले के कुछ हिस्सों में अवैध सिलिका रेत खनन पर एक याचिका की सुनवाई कर रहा है। याचिका में दावा किया गया है कि खनन की उपयुक्त प्रक्रिया का पालन किए बिना अनधिकृत खनन के कारण लोगों के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा पैदा हो रहा है और उन्हें सिलिकोसिस सहित कई बीमारियां हो रही हैं। सिलिकोसिस फेफड़े से जुड़ी बीमारी है जो बड़ी मात्रा में सिलिका धूल के फेफड़े में प्रवेश करने के कारण होती है। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की पीठ ने 29 नवंबर के आदेश में, पर्यावरण मानदंडों का उल्लंघन करने को लेकर 12 निजी पट्टाधारकों को मुआयना देने का निर्देश दिया। पीठ ने 14 निजी पट्टाधारकों को सिलिका धुलाई संयंत्र में भूजल के अवैध दोहन के लिए जुर्माना भरने का भी आदेश दिया। पीठ में न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल भी हैं। अधिकरण ने कहा, उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) संबद्ध विभागों के साथ समन्वय कर उन इलाकों में विशिष्ट स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करने के लिए तत्काल कदम उठाए, जहां सिलिका रेत खानों का संचालन खनन पट्टा धारकों द्वारा किया जा रहा है। अधिकरण ने संबंधित अधिकारियों को पीड़ित श्रमिकों के उपचार एवं रोगों की रोकथाम के लिए आवश्यक चिकित्सा बुनियादी ढांचे की तत्काल व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया। उसने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को विस्तृत दिशानिर्देश तैयार करने का भी निर्देश दिया, जिनका पालन संबंधित वैधानिक नियमकों द्वारा सिलिका रेत खानों और सिलिका रेत धुलाई संयंत्रों के लिए अनुमति या सहमति प्रदान करते समय किया जाए।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता और साइबर सुरक्षा पर संगोष्ठी

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय के कंप्यूटर विज्ञान विभाग ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता और साइबर सुरक्षा का अभिसरण: भविष्य के लिए शासन, उद्योग और शिक्षा जगत का रूपान्तरण विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन कर अंतरराष्ट्रीय साइबर सुरक्षा दिवस मनाया। इस संगोष्ठी में तीन पैनाल चर्चाएं हुईं, जिनका ध्यान क्रमशः शासन, उद्योग, और शिक्षा पर केंद्रित था। स्वागत भाषण में, विभागाध्यक्ष डॉ. पुनीत मिश्रा ने कहा कि वर्तमान समय में अकादमिक और अनुसंधान के क्षेत्र में सबसे क्रान्तिकारी क्षेत्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और साइबर सुरक्षा हैं। इनका अभिसरण न केवल डिजिटल सुरक्षा के प्रति हमारी सोच को बदल रहा है, बल्कि समाज के लिए अभूतपूर्व अवसर और चुनौतियाँ भी पैदा कर रहा है। प्रो. मनुका खन्ना ने कागज आधारित शासन से इलेक्ट्रॉनिक प्रशासन की ओर बदलाव और इससे जुड़े सुरक्षा मुद्दों पर ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने आधुनिक साइबर अपराधों पर चिंता व्यक्त की और उन्हें प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के उपाय सुझाए। उन्होंने कहा कि साइबर सुरक्षा डिजिटल प्रशासन का आधार है। सेवानिवृत्त आईएएस संतोष कुमार द्विवेदी ने डिजिटल बुनिया के बदलते परिदृश्य पर चर्चा करते हुए कहा कि आने वाले वर्षों में प्रौद्योगिकी एक गेम-चेंजर साबित होगी। सेवानिवृत्त आईएएस चंद्रिका प्रसाद तिवारी ने कहा कि नीति निर्माताओं को एआई गवर्नंस के लिए पारदर्शी, नैतिक और समावेशी ढांचे प्राथमिकता देनी चाहिए। डॉ. भुवनेश्वर जोशी ने कहा कि एआई-संचालित तकनीकी बुनियाद आवश्यक होने के साथ-साथ डायवनी भी हो सकती है। उन्होंने एआई के उन्नत रूपों और उनके संभावित खतरों पर चर्चा की। डॉन विशेषज्ञ मिलिंद राज ने उद्योगों में एआई-संचालित साइबर सुरक्षा समाधान विकसित करने और छात्रों को इसके लिए स्टार्टअप शुरू करने की प्रेरणा दी। स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉ। राकेश श्रीवास्तव ने स्पष्टीकरण सेवान में एआई के अनुप्रयोगों पर प्रकाश डाला। प्रोफेसर अरुणाम मुखोपाध्याय ने शैक्षणिक संस्थानों को एआई और साइबर सुरक्षा के नैतिक आयामों पर ध्यान केंद्रित करने और अंतर-विषयक अनुसंधान को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता बताई। विज्ञान संचारक डॉ. वीपी सिंह ने कहाकि साइबर अपराधों पर लगाम के लिए व्यापक कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए, जिससे लोग जागरूक हो सकें। कार्यक्रम का संचालन डॉ. किरणलता डंगवाल ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन डॉ. एस.पी. कर्नौजिया ने दिया।

हवाई अड्डों के सामने आने वाली चुनौतियों को रेखांकित करते हैं। दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया के शीर्ष 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में शुमार है। 2023 में, इसने लगभग 72.2 मिलियन यात्रियों की मेजबानी की और इसके तीन टर्मिनलों में वार्षिक यात्री हैंडलिंग क्षमता 100 मिलियन रही। इस पहल पर टिप्पणी करते हुए डायल के सीईओ विदेह कुमार जयपुरियार ने कहा, डायल दिल्ली हवाई अड्डे पर यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहा है। इस नई पहल को लागू करके, डायल का लक्ष्य कोहरे/मौसम या तकनीकी समस्याओं से प्रभावित उड़ानों के यात्रियों के लिए उतारने और चढ़ने की प्रक्रिया में लगने वाले समय को काफी कम करना है।

पार्किंग...

ही जमानत पर रिहा कर दिया गया। जमानत पर रिहा होने के दो दिन बाद ही भसीन इलाके में आया और सिंह को गाली दी और धमकाया। सिंह ने कहा, हमने पुलिस से शिकायत की। हालांकि, वह करीब एक महीने तक वहां से भागता रहा।

गिनी में फुटबॉल मैच के दौरान भगदड़ में 56 लोगों की मौत

भाषा । कोनाक्रो (गिनी)

दक्षिणी गिनी के एक फुटबॉल स्टेडियम में प्रशंसकों के बीच झड़प के बाद मची भगदड़ में 56 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। गिनी की सरकार ने सोमवार को यह जानकारी दी। संचार मंत्री फना सोमहा ने राष्ट्रीय टेलीविजन पर दिए गए एक बयान में कहा कि अधिकारी रविवार को हुई भगदड़ की इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों का पता लगाने के वास्ते जांच कर रहे हैं। अफ़्रीकी देश गिनी के सबसे बड़े शहर में भीड़ से खचाखच भरे स्टेडियम में फुटबॉल मैच के दौरान हुई झड़प के बाद भगदड़ मचने से बच्चों समेत कई फुटबॉल प्रशंसकों की मौत हो गई तथा कई अन्य घायल हो गए।



स्थानीय मीडिया और राजनीतिक पार्टियों के एक गठबंधन ने यह जानकारी दी। सुरक्षा बलों ने झड़प को शांत करने का प्रयास किया। गिनी के प्रधानमंत्री अमादी ओरी बाद ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर बताया कि गिनी के सैन्य नेता मामादी डौबोबी के सम्मान में रविवार दोपहर को आयोजित स्थानीय टूर्नामेंट के फाइनल के दौरान भगदड़ की यह

घटना हुई। नेजेरेकोर शहर में लेबे और नेजेरेकोर की टीम के बीच यह मैच हो रहा था। बाह ने कहा, भगदड़ के दौरान पीड़ितों की संख्या दर्ज की गई थी। हालांकि उन्होंने मारे गए लोगों की संख्या के बारे में कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय अधिकारी इलाके में शांति बहाल करने के लिए काम कर रहे हैं। नेशनल अलायंस फॉर अस्टब्लेशन एंड

डेमोक्रेसी नामक राजनीतिक दलों के गठबंधन ने एक बयान में कहा कि भगदड़ के कारण कई लोग मारे गए और घायल हुए। स्थानीय मीडिया ने बताया कि झड़प के कारण मची भगदड़ के बाद उत्पन्न अराजकता की स्थिति को काबू में करने तथा शांति को बहाली के लिए सुरक्षा बलों ने आंसूगैस का प्रयोग करने का प्रयास किया। स्थानीय मीडिया के अनुसार, इस कार्वाई से फुटबॉल प्रशंसक नाराज हो गए और उन्होंने पथरबाजी शुरू कर दी। ी कारण सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल किया। मीडिया गिनी ने बताया कि घटना में मारे गए लोगों में बच्चे भी शामिल हैं। वहीं अस्पताल में इलाज कर रहे कुछ घायलों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है।

अमेरिकः अलास्का के समुद्र में मछुआरों की नौक पलटी, पांच लोग लापता

वाशिंगटन। अलास्का की राजधानी जुनो के समीप खराब मौसम के बीच मछुआरों की एक नौका के समुद्र में पलट जाने से पांच लोग लापता हो गए और उनकी तलाश की जा रही है। अमेरिकी तटरक्षक बल ने रविवार को यह जानकारी दी।तटरक्षक बल की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, लगभग 50 फुट लंबी नौका विंड वॉकर के चालक दल ने रात 12 बजकर 10 मिनट पर संदेश भेजा कि उनकी नौका पलटने वाली है, लेकिन इसके अलावा और कुछ जानकारी नहीं दे पाया। बाद में पता चला कि विंड वॉकर , जुनो के दक्षिण-पश्चिम में पॉइंट कुवर्डन के पास पानी में पलट गई।विज्ञप्ति के अनुसार, एएमएचएस हबर्ड नौका के चालक दल ने यह संदेश सुना और वे घटनास्थल पर सबसे पहले पहुंचे। बचाव कार्य के लिए तटरक्षक बल ने एक एमएच-60 जेहॉक हेलीकॉप्टर और एक नौका को मौके पर भेजा।

ऑस्ट्रेलिया में मछुआरों की नौक से 2.3 टन केवीन जत्त, 13 लोग गिरफ्तार

वेलिंगटन। ऑस्ट्रेलिया में पुलिस ने ब्रॉसलैंड टट के पास क्षतिग्रस्त हुई संदिग्धों की एक नौका पर छापा मारकर करीब 2.3 टन कोकोन जब्त की और 13 लोगों को गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। संघीय पुलिस ने एक बयान में कहा कि इन मादक पदार्थों का बाजार मूल्य 76 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर था। जांच अधिकारियों ने ब्रिसबेन में पत्रकारों को बताया कि ए मादक पदार्थ किसी अज्ञात दक्षिण अमेरिकी देश से लाए गए थे। ऑस्ट्रेलियाई संघीय पुलिस कमांडर स्टीफन जे ने बताया कि कोमांचेरोस मोटरसाइकिल गिरोह द्वारा तस्करी की साजिश रचे जाने के संबंध में सूचना मिली थी और एक माह से की जा रही जांच के बाद शनिवार और रविवार को ए गिरफ्तारियां की गईं।

हसीना के समर्थकों की रैली पर ग्रेनेड हमला मामले में जिया के बेटे, 48 अन्य बरी हुए

ढाका। बांग्लादेश के उच्च न्यायालय ने 2004 में एक राजनीतिक रैली पर ग्रेनेड हमला मामले में अपने फैसले को पलटते हुए पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारीक रहमान और 48 अन्य को रविवार को बरी कर दिया।व्यह फैसला ऐसे समय में आया है जब बांग्लादेश में राजनीतिक उठापटक देखी जा रही है। इसी साल बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर छात्रों के विद्रोह के बाद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस संघर्ष में सैकड़ों लोग मारे गए थे।हंदन में स्व-निर्वास के दौरान रहमान ने जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर भी काम किया और उनकी पार्टी के सला में आने पर वह बांग्लादेश के अगले नेता बन सकते हैं।रहमान और 48 अन्य को शेख हसीना के समर्थकों द्वारा आयोजित एक रैली पर ग्रेनेड से हमला करने के मामले में 2018 में दोषी ठहराया गया था। इस हमले में 24 लोगों की जान चली गई थी और लगभग 300 लोग घायल हो गए थे। उस समय हसीना विश्व में थीं। अदालत ने अपने फैसले में 19 दोषियों को मृत्यु दंड और रहमान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

बाइडन ने अपने बेटे हंटर को माफी दी, कहा- आरोप राजनीति से प्रेरित थे

भाषा। वाशिंगटन

अमेरिका के निवर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडन ने अपने बेटे हंटर बाइडन के लिए रविवार को एक पूर्ण एवं बिना शर्त माफी जारी करते हुए कहा कि उन्हें सिर्फ इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वह उनके बेटे हैं। बाइडन ने रविवार रात को एक बयान में कहा, अपने पूरे करियर में मैंने एक ही सिद्धांत का पालन किया है: अमेरिकी लोगों को सच बताएं। वे निष्पक्ष होकर सोचेंगे। सच यह है कि मैं न्याय प्रणाली में विश्वास करता हूं, लेकिन मैं इससे जूझ चुका हूं और मुझे यह भी लगता है कि अनुभवहीन राजनीति ने इस प्रक्रिया को संक्रामित कर दिया है जिससे न्याय का उपहास हुआ है। मैंने इस सप्ताहांत इस आशय का निर्णय लिया, ऐसे में इसमें देरी करने का कोई मतलब नहीं था। बाइडन से मैंने पदभार लेने के सदस्यों के लाभ के लिए राष्ट्रपति पद की असाधारण शक्तियों का उपयोग नहीं करने के अपने पिछले वादों को पलटते हुए, रविवार रात बेटे हंटर को माफ कर दिया, जिससे वह संघीय गुंडागर्दी बंदूक और कर दोषों के लिए संभावित जेल की सजा से



बच गए। हंटर बाइडन को इस वर्ष की शुरुआत में संघीय बंदूक और कर अभियां में दोषी ठहराया गया था तथा उन्हें जल्द कैलिफोर्निया के डेलन में पेश होना था, जहां उन्हें लंबी, जेल की सजा हो सकती थी। जो बाइडन ने कहा, जिस दिन से मैंने पदभार संभाला है, मैंने यही कहा था कि मैं न्याय विभाग के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करूंगा और मैंने अपना वचन निभाया। मैंने यह भी देखा कि बेटे हंटर पर चुनिंदा और अनुचित तरीके से मुकदमा चलाया जा रहा है। यूेमोक्रेटिक राष्ट्रपति ने पहले कहा था कि वह अपने बेटे को डेलावेयर और कैलिफोर्निया के दो मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद उसे माफ नहीं करेंगे या उसकी सजा कम नहीं करेंगे।

संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष न्यायालय में जलवायु परिवर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई शुरू

भाषा। हेग (नीदरलैंड)

संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष न्यायालय ने जलवायु परिवर्तन का मुक़ाबला करने और इसके विनाशकारी प्रभाव का अधिक सामना करने वाले देशों के लिए इससे निपटने के वास्ते कानूनन आवश्यक उपायों से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई सोमवार को शुरू की। मामले की सुनवाई दो सप्ताह तक चलेगी और इसे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के इतिहास के सबसे अधिक बड़ा मामला बताया जा रहा है। समुद्र के बढ़ते जल स्तर के कारण विलुप्त हो सकने के खतरे का सामना कर रहे द्वीपीय राष्ट्रों के अपना अस्तित्व बचाने की वर्षों की कवायद के बाद, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पिछले साल अंतरराष्ट्रीय न्यायालय से जलवायु परिवर्तन के संबंध में देशों के दायित्व पर विचार मांगा था। अदालत का कोई भी फैसला गैर-बाध्यकारी परामर्श हो सकता है और अमीर देशों को जलवायु परिवर्तन के खतरे का



के अपना अस्तित्व बचाने की वर्षों की कवायद के बाद, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पिछले साल अंतरराष्ट्रीय न्यायालय से जलवायु परिवर्तन के संबंध में देशों के दायित्व पर विचार मांगा था। अदालत का कोई भी फैसला गैर-बाध्यकारी परामर्श हो सकता है और अमीर देशों को जलवायु परिवर्तन के खतरे का

दीर्घकालिक कोविड लंबे संक्रमण की वजह से हो सकता है

भाषा। मेलबर्न

कोरोना वायरस संक्रमण से प्रस्त लम्बग 5-10 प्रतिशत लोग लंबे समय तक कोविड का सामना करते हैं, जिसके लक्षण तीन महीने या उससे अधिक समय तक रहते हैं। अनुसंधानकर्ताओं ने लंबे समय तक कोविड रहने की व्याख्या करने के लिए कई जैव प्रणालियां प्रस्तावित की हैं। हालांकि, ऑस्ट्रेलिया के नवीनतम मेडिकल जर्नल में प्रकाशित एक आलेख में, हमारा तर्क है कि यदि सभी नहीं तो अधिकतर लोगों में लंबे समय तक कोविड का होना शरीर में वायरस के लंबे समय तक बने रहने से जुड़ा प्रतीत होता है। महामारी की अन्वेषाकृत शुरुआती अवधि से, यह मान्यता रही है कि कुछ लोगों में, सार्स-सीओवी-2 वायरस या कम से कम उसके अवशेष लंबे समय तक विभिन्न जठकों और अंगों में बने रह सकते हैं। इस सिद्धांत को वायरल परसिस्टेंस के रूप में जाना जाता है। कुछ लोगों के शरीर में वायरस के अवशेषों की दीर्घकालिक उपस्थिति की बात अच्छी तरह से प्रमाणित हो चुकी है, लेकिन कम निश्चित बात यह है कि क्या कोई जीवित वायरस

लीडलेस पेसनेकर से मरीच को मिलेगा लाभ
पहली बार एक मरीच को मिना लीड वाला पेसनेकर लगाया गया है। प्रयोगाज के एक अस्पताल में 55 वर्षीय पुरुष मरीज के दिल में ध्विरी वीआरएन एक पेसनेकर का इन्प्लांट किया गया। उससे खास बात यह है कि इस प्रक्रिय के लिए न तो सर्जरी की जरूरत पड़ी और न ही शरीर पर किसी तरह का घीरा लगाया गया।यह लीडलेस पेसनेकर, पारंपरिक पेसनेकर के मुकाबले लगभग 90 प्रतिशत छोट है। पारंपरिक पेसनेकर में धातु पर घीरा लगाना पड़ता है और तब के नीचे बड़े डिवाइस को फिट करना होता है। हालांकि लीडलेस पेसनेकर में इन उपेधानियों का सामना नहीं करना पड़ता। इस तकनीक के जॉरि मरीच का दिल सामान्य तरीके से धड़कता है। इसके अलावाए इसकी बैटरी की लाइफ़ाजी लगभग 17 साल है जो इसे बेहद प्रभावी बनाती है। पेसनेकर उन मरीजों के लिए होता है जिनके दिल की गति धीमी से जाती है। पारंपरिक पेसनेकर तार वाले होते हैं।एनिलेक डीएनए के लिए होता है और वहीं से यह काम करता है। इस पेसनेकर के कारण न तो सर्जरी की आवश्यकता होती है न अस्पताल में कुछ दिन तकने कीए और न ही मरीज की गतिशीलता ,मोबिलिटीदंड पर असर पड़ता है।डॉ. ओमर मुस्ताफ़ ।हसन निदेशक,इंटरवैशनल कार्डियोलॉजी इलाहबाद हर्ट सेंटर प्रयोगाज ने यह जानकारी दी।मरीज को पहले एक पारंपरिक पेसनेकर लगाया था या लेकिन लीड्स के कारण उन्हें संक्रमण हो गया था। इस समस्या के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। लीडलेस पेसनेकर मात्र पांच घण्टा की एक छोटी सी वीएच एमिसे सीधे दिल के अंदर फिट किया जाता है।

लंबे समय तक बने रहता है और यदि ऐसा है, तो क्या यही लंबे समय तक कोविड का कारण है। यह भेद करना महत्वपूर्ण है क्योंकि जीवित वायरस को विशिष्ट एंटीवायरल तरीकों से लक्षित किया जा सकता है जबकि मृत वायरस अवशेषों के साथ ऐसा नहीं किया जा सकता। वायरल परसिस्टेंस यानी विषाणु के बने रहने के दो

दीर्घकालिक कोविड हो सकता है। अनुसंधान क्या कहता है? ऐसा कोई अध्ययन तो नहीं है जो पुष्टि करता हो कि लगातार वायरस का संक्रमण दीर्घकालिक कोविड का कारण है, लेकिन सामूहिक रूप से कई हालिया प्रमुख शोधपत्रों पर संचर्ष में एक इशारा करते हैं। फरवरी में, नेचर पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि कोविड के हल्के लक्षणों वाले बहुत से लोगों में वायरस की आनुवंशिक सामग्री, तथाकथित वायरल आरएनए उनके ध्रसन मार्ग से लंबे समय तक निकलते रहते। इस वायरल आरएनए के लगातार निकलने वाले लोगों में लंबे समय तक कोविड रहने का अधिक जोखिम था। अन्य प्रमुख शोधपत्रों में रोगियों के रक्त में उनके प्रारंभिक संक्रमण के कुछ वर्ष बाद वायरल आरएनए और प्रोटीन की प्रतिकृति का पता चला। यह संकेत है कि वायरस संभवतः शरीर में कुछ छिपे हुए हिस्सों में लंबे समय तक प्रतिकृति बना रहा है, जिसमें संभवतः रक्त कोशिकाएं भी शामिल हैं। एक अन्य अध्ययन में तीव्र संक्रमण के एक से चार महीने बाद दस अलग-अलग जगह स्थलों और रक्त के नमूनों में वायरल आरएनए होने का पता चला।

फ्रांस में स्की रिजॉर्ट के पास बस दुर्घटना में दो लोगों की मौत, 33 अन्य घायल

मैड्रिड। दक्षिणी फ्रांस के पिरिनी पर्वत शृंखला ने मौजूद एक स्की रिजॉर्ट के पास रविवार शाम हुई एक बस दुर्घटनाग्रस्त ने कम से कम दो लोगों की मौत हो गई और 33 अन्य घायल हो गए। स्थानीय अधिकारियों ने यह जानकारी दी।स्थानीय प्रशासन ने बताया कि पोर्ट-प्यूग्रेसो स्की रिजॉर्ट के पास जो बस दुर्घटनाग्रस्त हुई उसने चालक सहित कुल 47 लोग सवार थे। सात लोगों को अस्पताल में भर्ती करया गया है। उन्होंने बताया कि दुर्घटनाी जांच से पता चला है कि बस एक घट्टान से टकराने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हुई, लेकिन फिलहाल हदसे का वास्तविक कारण ज्ञात नहीं है।स्थानीय अतिनेशनल सेवा द्वारा जारी की गई तस्वीरो ने बस को एक घट्टान पास देखा जा सकता है और टक्कर के कारण वाहन का दाहिना भाग आंशिक रूप से धतिग्रस्त नजर आ रहा है तथा इसकी खिड़कियों के शीशे टूटकर बिखरे हुए थे। बचाव कार्य ने 120 से अधिक कर्मियों को लगाया था, जिनमें पड़ोसी स्की के कैंटोलोनिया और अनडोस के लोग भी शामिल थे। हेलीकॉप्टर भी तैनात किए गए। फ्रांस के परिवहन मंत्री फ्रांकोइस मोंटबुरे ने सोशल मीडिया पर एक्स पर जारी पोस्ट में पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की।स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि घायलों को टून्नूत्र, पैरिंगमन और फ्रेंक्स के फ़्रांसीसी अस्पतालों और कैंटोलोनिया के पुइसगॉर्ड स्थित अस्पताल ले जाया गया।

नेपाल सरकार ने चीन से दो करोड़ अमेरिकी डॉलर की अनुदान सहयता स्वीकार की

काठमांडू। नेपाल सरकार ने प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली की चीन यात्रा से पहले इस देश से अनुदान सहयता के रूप में दो करोड़ अमेरिकी डॉलर की परिशोधनाए स्वीकार की है। प्रधानमंत्री के तौर पर चौथी बार पदभार ग्रहण करने के बाद यह ओली की पहली चीन यात्रा है। सुचना एवं संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ ने रविवार को सार्वदाताओं से कहा कि ननिप्रिष्टव की बैठक में प्रधानमंत्री ओली की चीन यात्रा की सफलता की कामना की गई तथा चीन से अनुदान सहयता के रूप में दो करोड़ अमेरिकी डॉलर (लगभग 2.70 अरब नेपाली रुपए) की परिशोधनाओ को स्वीकार करने का निर्णय लिया गया। सरकारी प्रवक्ता गुरुङ के अनुसार, इसके अलावा मनिमंडल ने चीन सरकार द्वारा प्रस्तावित 5.60 अरब नेपाली रुपए मूल्य की परिशोधनाओ के लिए 30 करोड़ चीनी युआन (लगभग 41 लाख अमेरिकी डॉलर) की राशि स्वीकार करने का भी निर्णय लिया। नेपाल के प्रधानमंत्री ओली सोमवार को चीन की चार दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर खाना हुए। इस यात्रा के दौरान उनका चीन के राष्ट्रपति शि घिनफिंग के साथ आपसी हित के विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करने का कार्यक्रम है। विदेश मंत्रालय ने यह कस कि ओली अपने चीनी समकक्ष ली किंग के निमंत्रण पर बीजिंग की यात्रा कर रहे है।

कचरे के मूल्य पर 9वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित नई दिल्ली

नई दिल्ली। कचरे से मूल्य निर्माण पर सीआईआई के 9वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत सरकार के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री गृधेन्द्र यादव ने कहा कि हन्हें कचरे से मूल्य के सिद्धांत का मद्यन से प्रतिकूलता को अवसर में बदलने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के माननीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहाए कचरे से मूल्य पर सीआईआई के 9वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अपने संबोधन में, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री गृधेन्द्र यादव ने कहा कि जब हम विकसित भारत पर ध्यान केंद्रित करते है, तो हन्हें हरित और टिकाऊ भारत पर भी ध्यान देने की जरूरत है। एक सर्वगुणर सम्मेलनी का लक्ष्य उत्पाद डिजाइन से लेकर जीवन के अंत तक प्रबंधन तक ंहर घरण में रिसाइविलग, पुनः उपजोना और कचरे को काम करने पर ध्यान केंद्रित करके कचरे को कम करना है। लक्ष्य शून्य चक्रण प्राप्त करना और पर्यावरण.अनुकूल उत्पादन सुनिश्चित करना है। हन्हें ऐसे कुशल कार्यालय तैयार करने की जरूरत है जो परसंरक्षण, रिसाइविलग टेक्नोलॉजी व पर्यावरण अनुकूल उत्पाद डिजाइन में मदद करें। उन्हेहने कचरे को बोझ नहीं बल्कि संसाधन मानने की भी अपील की। उन्हेहने प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियमाए निर्माण और विधाय कचरा प्रबंधन विनियम बैटरी कचरा प्रबंधन विनियम ई कचरा प्रबंधन नियमाए राष्ट्र उद्योग अधिसूचना मोटर वाहन पंजीकरण और रक्षेण नीति आदि सहित कचरे से मूल्य से संबंधित कई सरकारी नीतियों पर प्रकाश डाला।

दुनिया में आईटी स्टोरेज सॉल्यूशंस पर जोर

ग्लोबल। हुडिया इनको सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, कांप्यूटिंग और मोबिलिटी उत्पादों के मुंबई में अग्रणी किंगेा और आईटी स्टोरेज सॉल्यूशंस में अग्रणी ईवीएन ब्रांड ने एसएसी, ऐन और अन्य उत्पायुक्तिक सगणानों के लिए भारत के सीईओ महेन्द्र-इन-इंडिया स्टोरेज के लॉन्च की गर्व के साथ घोषणा की है। यह लॉन्च ऐतिहासिक रूप से नील का पाथर है, क्योंकि ईवीएन स्थानीय रूप से विकसित और निर्मित नेड इन इंडिया स्टोरेज समाधान पेश करने वाला पहला भारतीय ब्रांड बन गया है।ईवीएन इंडिया के प्रबंध निदेशक कुणाल हुडिया ने कहा कि यह एक उत्तम लॉन्च से कहीं अधिक है, नैतिक तकनीक क्षेत्र में भारत की धमती की घोषणा करना। ईवीएन के अगले समय में अपने उत्पाद पोर्टफोलियो का विस्तार करते हुए स्थानीय रूप से निर्मित उत्पादन समाधानों को पेश करके इस गति को बनेने की योजना बना रहा है। ईवीएन इंडिया के सीईओ विशाल हुडिया ने कहा कि ईवीएन का हमने से भारतीय उद्योगकारों को सशक्त बनाने का उद्देश्य रहा है। ये नेड-इन-इंडिया स्टोरेज समाधान इस बात की पुष्टि करते है कि भारतीय नवाचार वया हासिल कर सकते है। एक भारतीय ब्रांड के रूप में, हन्हें अन्य अंतरराष्ट्रीय ब्रांडों के समाधान गुणवत्ता के साथ भारतीय आवश्यकताओं के अनुकूल उच्च गुणवत्ता वाले स्टोरेज समाधान पेश करने पर गर्व है।यह एक बदलाव लाने के बारे में है।

नेपाल के पीएम ओली चीन की यात्रा पर रवाना

काठमांडू। नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली सोमवार को चीन की चार दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रवाना हुए। इस यात्रा के दौरान उनका चीन के राष्ट्रपति शि घिनफिंग के साथ आपसी हित के विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करने का कार्यक्रम है। अपने कार्यक्रमाले ने ओली की किसी पड़ोसी देश की यह पहली यात्रा है। यह विदेश मंत्रालय ने कहा कि ओली अपने चीनी समकक्ष ली किंग के निमंत्रण पर बीजिंग का दौरा कर रहे है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री ओली दो से पांच दिसंबर की अपनी यात्रा के दौरान बीजिंग में चीन के राष्ट्रपति शि घिनफिंग से अनुकूल चर्चेंगे और आपसी हित के मामलों पर चर्चा करेंगे के लिए प्रधानमंत्री ओली की साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वह चीन में 39 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के नेता के रूप में रहेंगे। इस यात्रा पर उनकी पहली राधिक साक्षर भी उनके साथ है। ओली नेशनल पीपुल्स कंग्रेस की स्थाई समिति के अध्यक्ष झाओ लेंजी से भी मुलाक़ात करेंगे और वह बीजिंग स्थित पेंकिंग विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्य वक्ता होंगे।

कुवैत में फंसे भारतीय यात्री नैनचेस्टर के लिए रवाना

कुवैत सिटी। नैनचेस्टर जाने वाली गल्फ एयर की उड़ान के कई भारतीय यात्री कुवैत हवाई अड्डे पर लगभग 20 घंटे तक फंसे रहने के बाद सोमवार सुबह गंतव्य के लिए रवाना हो गए। बहरीन से नैनचेस्टर जाने वाली गल्फ एयर की उड़ान को रविवार को अज्ञात कुर्म जिले के सार्थ कुवैत की ओर मोड़ दिया गया था।हखर के अनुसार गल्फ एयर जीएफ़न ने एक दिसंबर को स्थानीय समय के अनुसार देर रात दो बजकर पांच निमाट पर बहरीन से उड़ान भरी, लेकिन विमान को कुछ खराबी आ जाने के कारण उसे सुबह चार बजकर एक निमनट पर कुवैत में उतराना पड़ा। सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट के अनुसार, कई यात्रियों ने शिकवारी की कि वे घंटे हवाई अड्डे पर फंसे रहे, जिसके बाद कुवैत ने भारतीय दूतावास ने गल्फ एयर के अधिकारियों के समक्ष इस मामले को उठाया।

पाकिस्तान के कुर्म में संघर्ष विराम हुआ

पेशावर। पाकिस्तान के अशांत खैबर पख्तूनख़्वा प्रांत ने दो ख़ासरीन समूहों के बीच कई दिनों तकची झड़पों के बाद संघर्ष विराम समझौता हो गया है। इन झड़पों में अशांत कुर्म जिले में 130 लोग मारे गए थे।कुर्म के उग्रवात जावेदुर्रएल महसूद ने रविवार को अज्ञात कुर्म जिले के सार्थ वाले क्षेत्रों में शांति स्थापित होने की पुष्टि की।जिले में अलीगं और बागान क़्बायली समूहों के बीच संघर्ष 22 नवंबर को तब शुरू हुआ, जब पारशियान और एक दिन पहले यात्री डेन के काफ़िले पर हमला हुआ, जिसमें 47 लोग मारे गए थे। गंभीर रूप से घायल हुए कई यात्रियों ने बाद में दम तोड़ दिया, जिससे मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 151 हो गई। कुर्म जिले में लगातार 11 वे दिन झड़प जारी रही, जिससे हिसा ने मरने वाले की संख्या बढ़कर 130 हो गई है। रविवार को ही कम से कम छह लोग मारे गए और आठ घायल हो गए थे।

माली के सैन्य शासन के ड्रोन हमले में आठ तुआरेग विद्रोहियों को मार गिराया

बनाको (माली)। माली के सैन्य शासन ने डेश के उत्तरी भाग में स्थित निजाउत्तनिन शहर से आठ तुआरेग विद्रोही नेताओं को मार गिराया। विद्रोही समूहों के प्रवक्ता ने रविवार को यह जानकारी दी। वर्ष 2012 में विद्रोह शुरू होने के बाद यह पहली बार है जब एक ही हमले में इतनी संख्या में तुआरेग नेता मारे गए। प्रवक्ता मोहम्मद एमनाउल्लाह रमदान ने एक बयान में कहा, एक दिसंबर को अल्गीरियाई सीमा के पास तिनाग इलाक़े में कई समर्थित ड्रोन हमलों ने कुछ आतंसार नेता शहीद हो गए। अजादाद क़्बा इस्तेमाल अलगाववादी नेता उत्तरी माली के लिए इस्तेमाल करते हैं। अलगाववादिियों के बयान में आठ तुआरेग नेताओं के नाम का फ़िर्क है, गिनने सबसे मनुष्य तुआरेग सहाय समूह गैटिया के महासचिव फ़हद एव अल महगूद का नाम शामिल है।

